

बृहस्पतिवार 18.12.2025

समय 1830

मुख्य समाचार :-

- लोकसभा में विकसित भारत –जी राम जी विधेयक 2025 पारित।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने भूलेख पोर्टल को एक जनवरी से शुरू करने को कहा।
- हल्द्वानी में कुमाऊं का पहला और राज्य का दूसरा जेन-जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ।

विकसित भारत –जी राम जी

लोकसभा ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण – जी-राम-जी- विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी विधेयक लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की गति को ओर बढ़ावा देगा। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।

संयुक्त सहकारी खेती

पौड़ी जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड पाबौ में ढिकवाली की साधन सहकारी समिति ने पहली बार संयुक्त सहकारी खेती के तहत फलोरीकल्चर की शुरुआत की है। अक्टूबर 2025 से शुरू हुई इस परियोजना में अब तक गुलदावरी एवं ग्लेडियस के फूलों को दिल्ली और देहरादून की मंडियों में बेचकर समिति को 3 लाख 52 हजार की आय प्राप्त हुई है। इस संयुक्त सहकारी खेती से 41 किसान जुड़े हैं। परियोजना को गति देने के लिए सहकारिता विभाग की संचालित राज्य समिति सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत 7 लाख 57 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जिला प्रशासन ऐसे नवाचारों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाए। रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का उचित मूल्य दर्ज हो इसकी जांच के लिए संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। उन्होंने तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाने को कहा।

10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी। बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि बोर्ड की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 15 फरवरी तक चलेंगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चकृत

शासन ने ऊधमसिंह नगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म को उच्चकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का शासनादेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 30 शैक्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इसके लिए कुल 32 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें 20 नियमित और 12 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी

प्रदेश में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 का शुभारंभ 23 दिसंबर से किया जाएगा। इसमें कुल 26 खेल स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिता को लेकर सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र और राज्यस्तरीय पर चार चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का समापन 28 जनवरी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी विजेता को पांच लाख की धनराशि दी जाएगी। श्रीमती आर्य ने बताया कि सांसद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को दो लाख और विधानसभा ट्रॉफी जीतने वाली टीम को एक लाख रुपये की नकद इनाम दिया जाएगा।

खेल मंत्री ने बताया कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर खिलाड़ी को एक लाख की अतिरिक्त इनाम की राशि दी जाएगी। अब तक एक लाख 10 हजार से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर तक होगा। खेलमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी की स्पर्धा अलग से आयोजित की जाएगी।

भूलेख पोर्टल

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को भूलेख पोर्टल को एक जनवरी और आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण के सम्बन्ध में एनआईसी, आईटीडीए एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज होते ही व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो जाए। साथ ही आर ओ आर में परिवर्तन होते ही स्वतः सजरे में भी स्टेटस परिवर्तन हों। मुख्य सचिव ने राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित करने को कहा, ताकि मामलों के निस्तारण में तेजी आ सके।

राज्य का दूसरा जेन-जी पोस्ट ऑफिस

हल्द्वानी में भारतीय डाक विभाग ने कुमाऊं का पहला और राज्य का दूसरा जेन-जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया। एमबीपीजी कॉलेज परिसर में स्थापित कुमाऊं के पहले जेन-जी पोस्ट ऑफिस का निदेशक डाक सेवा, उत्तराखंड परिमंडल अनसूया प्रसाद चमोला ने उद्घाटन किया। श्री चमोला ने बताया कि जेन-जी पोस्ट ऑफिस खोलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवाओं को आधुनिक बनाना है, ताकि जेन-जी युवाओं को डाक सेवाओं की ओर आकर्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस जेन-जी पोस्ट ऑफिस में युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्री वाई-फाई, कैफे, मिनी लाइब्रेरी, डिजिटल भुगतान की सुविधा और इंटरनेट के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

जनजागरूकता अभियान

ऊधम सिंह नगर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जन स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विभिन्न नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के के अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान के नाम से इस रैली को निकाला गया है।